



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-09122023-250512
CG-DL-W-09122023-250512

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 9—दिसम्बर 15, 2023 (अग्रहायण 18, 1945)
No. 49] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 9—DECEMBER 15, 2023 (AGRAHAYANA 18, 1945)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.		पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	657	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1131	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	11	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	2291	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	2515
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	183
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	4447
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्क.....	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	657	(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1131	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	11	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	2291	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	2515
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	183
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	4447
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

शिक्षा मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 नवंबर 2023

सं. 9-4/2022-यू3 (ए)—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत यूजीसी की सलाह पर उच्च शिक्षण संस्थान को सम विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषित करने का अधिकार प्राप्त है।

2. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत भारतीय वन प्रबंध संस्थान (आईआईएफएम), नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश को, डी-नोवो श्रेणी के तहत सम विश्वविद्यालय संस्थान का दर्जा प्रदान करने के लिए यूजीसी पोर्टल पर दिनांक 12.08.2022 को एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया था। यूजीसी से आवेदन की जांच करने और यूजीसी (समवत विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2019 के अनुसार अपनी सलाह देने का अनुरोध किया गया था।

3. और जबकि, यूजीसी ने अपने पत्र संख्या 29-5/2022 (सीपीपी- I/डीयू) दिनांक 07.12.2022 के तहत सूचित किया कि एक विशेषज्ञ समिति के माध्यम से प्रस्ताव की जांच की गई थी। समग्र मूल्यांकन के बाद, समिति ने ज्ञान के अद्वितीय और उभरते क्षेत्रों में निम्नलिखित प्रस्तावित पाठ्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए कुछ शर्तों के साथ आशय पत्र (एलओआई) जारी करने की सिफारिश की:

- i. वानिकी प्रबंधन में पीजी कार्यक्रम,
- ii. वहनीयता प्रबंधन में पीजी कार्यक्रम,
- iii. विकास एवं सतत वित्त में पीजी कार्यक्रम
- iv. जलवायु लोचशीलता एवं कार्बन प्रबंधन में स्नातकोत्तर कार्यक्रम
- v. संरक्षण और आजीविका में पीजी कार्यक्रम,
- vi. सतत विकास में पीजी कार्यक्रम।

4. और जबकि, यूजीसी विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर आयोग द्वारा दिनांक 22.11.2022 को आयोजित अपनी 563वीं बैठक (मद संख्या 2.10) में विचार किया गया था और अनुमोदित किया गया था। यूजीसी की सलाह पर विचार करते हुए, मंत्रालय ने तीन वर्ष की अवधि के भीतर निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के लिए भारतीय वन प्रबंध संस्थान (आईआईएफएम), नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश को दिनांक 27.12.2022 को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया:

- i. आईआईएफएम, भोपाल उभरते क्षेत्रों में प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार करेगा;
- ii. आईआईएफएम, भोपाल अपेक्षित योग्यता वाले संकाय की भर्ती करेगा;
- iii. आईआईएफएम, भोपाल प्रस्तावित स्कूल के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करेगा;
- iv. संस्थान अपनी डीपीआर, कार्यनीतिक विजन योजना और रोलिंग कार्यान्वयन योजना को तदनुसार संशोधित करेगा;
- v. संस्थान मध्य प्रदेश राज्य सरकार से एनओसी/अभिमत प्राप्त करेगा।
- vi. आईआईएफएम, भोपाल संस्थान को समवत विश्वविद्यालय घोषित किए जाने के बाद भी निरंतर वित्तीय सहायता के संबंध में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से प्रतिबद्धता पत्र प्रस्तुत करेगा।

5. और इसके अलावा जबकि, संस्थान द्वारा अपने पत्र संख्या आईआईएफएम/डीआईआर/एसीए.24/2023/140 दिनांक 17.08.2023 के तहत आशय पत्र की शर्तों के अनुसार प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट को यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा सत्यापित और स्वीकार किया गया था। आयोग ने दिनांक 03.11.2023 को आयोजित अपनी 574वीं बैठक (मद सं. 2.09) में यूजीसी विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर विचार किया और मंजूरी दे दी।

6. अब, इसलिए, यूजीसी की सलाह पर, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय वन प्रबंध संस्थान (आईआईएफएम), नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश को पांच वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए डी-नोवो श्रेणी के तहत एक समवत विश्वविद्यालय संस्थान घोषित करता है। उक्त घोषणा निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

- i. भारतीय वन प्रबंध संस्थान (आईआईएफएम), भोपाल इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से छह वर्ष की अवधि के भीतर यूजीसी (समवत विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 का अनुपालन करेगा;
- ii. भारतीय वन प्रबंध संस्थान (आईआईएफएम), भोपाल की समवत विश्वविद्यालय दर्जे की पुष्टि मौजूदा विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, आयोग की समीक्षा और सलाह के आधार पर पांच वर्ष के बाद की जाएगी।
- iii. इस अधिसूचना के एक वर्ष के भीतर संपूर्ण चल और अचल परिसंपत्तियां कानूनी रूप से भारतीय वन प्रबंध संस्थान (आईआईएफएम), भोपाल के नाम पर स्थानांतरित कर दी जाएगी।
- iv. यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना, समवत विश्वविद्यालय संस्थान/या इसकी घटक शिक्षण इकाइयों की परिसंपत्तियों या निधियों/राजस्व का कोई विचलन नहीं किया जाएगा।
- v. भारतीय वन प्रबंध संस्थान (आईआईएफएम), भोपाल ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो वाणिज्यिक और लाभ कमाने वाली प्रकृति की हो।
- vi. भारतीय वन प्रबंध संस्थान (आईआईएफएम), भोपाल में पेश किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों/निकायों द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप होंगे।
- vii. भारतीय वन प्रबंध संस्थान (आईआईएफएम), भोपाल समय-समय पर यूजीसी द्वारा जारी मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार ही इस विषय पर नए शैक्षणिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम, ऑफ-कैंपस, ऑफ-शोर कैंपस शुरू करेगा।
- viii. भारतीय वन प्रबंध संस्थान (आईआईएफएम), भोपाल अनुसंधान कार्यक्रमों के साथ-साथ डॉक्टरल और नवोन्मेषी शैक्षणिक कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए समुचित कदम उठाएगा। संस्थान केवल वर्तमान में नए उभरते क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहेगा, अपितु यूजीसी विनियमों/दिशानिर्देशों के साथ-साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार करने का प्रयास करेगा।
- ix. भारतीय वन प्रबंध संस्थान (आईआईएफएम), भोपाल राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) द्वारा वैध प्रत्यायन हेतु नियत सभी पात्र अकादमिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों को प्राप्त करने के लिए सभी अपेक्षित कदम उठाएगा और संस्थान समय-समय पर यथासंशोधित यूजीसी (समविश्वविद्यालय संस्थान) विनियम 2023 में यथा निहित प्रावधानों के संदर्भ में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, जैसा भी मामला हो, द्वारा वैध प्रत्यायन प्राप्त करेगा।
- x. छात्रों के प्रवेश, छात्रों की प्रवेश क्षमता, शैक्षणिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अनुमोदन का नवीनीकरण, छात्रों की प्रवेश क्षमता में संशोधन, नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम शुरू करने आदि के मामले में संबंधित सांविधिक परिषदों के सभी निर्धारित मानदंड और प्रक्रियाएं प्रभावी रहेंगी और भारतीय वन प्रबंध संस्थान (आईआईएफएम), भोपाल द्वारा उनका पालन किया जाएगा।
- xi. भारतीय वन प्रबंध संस्थान (आईआईएफएम), भोपाल अपने संशोधित संगम ज्ञापन (एमओए)/नियमों को यूजीसी (समविश्वविद्यालय संस्थान), 2023 के प्रावधानों के अनुसार यूजीसी/शिक्षा मंत्रालय को जून, 2024 तक प्रस्तुत करेगा। जब भी आवश्यक होगा, संस्थान प्रचलित विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अपने संगम ज्ञापन/नियमों को अद्यतन या उनमें संशोधन या परिवर्तन करेगा।
- xii. भारतीय वन प्रबंध संस्थान (आईआईएफएम), भोपाल यूजीसी के नियमों एवं विनियमों और संबंधित सांविधिक परिषदों के अनुसार शुल्क संरचना का पालन करेगा।
- xiii. भारतीय वन प्रबंध संस्थान (आईआईएफएम), भोपाल इस मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) द्वारा जारी वार्षिक भारतीय रैंकिंग में भाग लेगा।

- xiv. भारतीय वन प्रबंध संस्थान (आईआईएफएम), भोपाल अनिवार्य रूप से एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी), अपने छात्रों की पहचान बनाएगा और उनके क्रेडिट स्कोर को डिजिटल लॉकर में अपलोड करेगा एवं सुनिश्चित करेगा कि क्रेडिट स्कोर एबीसी पोर्टल पर प्रदर्शित हों एवं समर्थ ई-जीओवी को अंगीकृत करेगा।

अंबरीश कुमार शर्मा
अवर सचिव

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
नई दिल्ली – 110001, दिनांक 24 नवंबर 2023
आदेश

सं.: एसवाई-19014/6/2023-एसबीआर—पोत भंग संहिता (संशोधित), 2013 के पैरा 8.4.1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, एतद्वारा पोत भंग संहिता (संशोधित), 2013 के निम्नलिखित खंडों में इस आदेश की अनुसूची में दिए गए अनुसार संशोधन करता है:

प्रस्तावित संशोधन	एसबीसी में मौजूदा प्रावधान (संशोधित), 2013	संशोधन
अध्याय III में: पोत का आगमन, एंकरिंग और बीचिंग प्रक्रिया खण्ड क्रमांक 3.5 (ट) :-	पोत मालिक से यह वचन लेना कि वे बाहरी लंगरगाह पर पोत के लंगर डालने की तारीख से 7 दिनों के भीतर भारहीनता प्रमाण-पत्र जमा करेंगे। यह स्पष्ट किया गया है कि समुद्र तट की अनुमति राज्य समुद्री बोर्ड द्वारा केवल भारहीनता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही दी जाएगी।	"अध्याय VIII - विविध और दंड प्रावधान" के एसबीसी 2013 के खंड 8.3.5 (क) में पैराग्राफ को शामिल करने के लिए "पुनर्चक्रण से पहले अनुबंध VIII के अनुसार दिए गए प्रारूप में पोत मालिक/नकद खरीदार और पोत पुनर्चक्रणकर्ता के बीच एक नोटरीकृत क्षतिपूर्ति समझौता निष्पादित किया जाएगा, ताकि पोत पुनर्चक्रण के बाद के चरण में कोई भी दावा या समुद्री ग्रहणाधिकार न हो" संलग्न अनुबंध VIII के अनुसार क्षतिपूर्ति समझौता।
अध्याय VI में: पोत पुनर्चक्रण में शामिल हितधारकों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण अनुपालन के लिए सामान्य निर्देश। खण्ड संख्या 6.5.5: -	प्लॉट/यार्ड/अक्रिय क्षेत्र पर कोई भी सामग्री नहीं जलाई जाएगी।	इस मामले को नियंत्रित तापन, न कि जलने के रूप में लिया जाना चाहिए। निम्नलिखित पाठ को मौजूदा खंड 6.5.5 में जोड़ा जाना है "एक परमिट व्यवस्था के साथ काम के घंटों के बाद शाफ्टिंग को हटाने के लिए प्रोपेलर के हब का नियंत्रित तापमान रखना। काम करने के परमिट का प्रारूप अनुबंध IX के अनुसार है"।
अध्याय III में: पोत का आगमन, एंकरिंग और बीचिंग प्रक्रिया खण्ड 3.23	इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करने और पोत पर सभी बकाया/शुल्क के भुगतान के बाद यह, सीमा शुल्क प्राधिकरण शुल्क से मुक्त हो जाएगा और पोत को पुनर्चक्रण के लिए मंजूरी मिल जाएगी।	खंड 3.23 में हटाया जाने वाला पाठ: "इन सभी औपचारिकताओं के पूरा होने और पोत पर सभी बकाया/शुल्क के भुगतान के बाद यह सीमा शुल्क प्राधिकरण के शुल्क से बाहर हो जाएगा और पोत को पुनर्चक्रण के लिए मंजूरी मिल जाएगी"।
अध्याय III में: पोत का आगमन, एंकरिंग और बीचिंग प्रक्रिया खण्ड 3.18, 3.19 एवं 3.20	3.18: सीमा शुल्क प्रक्रियाएं: पोत पुनर्चक्रण को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक सभी दस्तावेज और विवरण भी लंगरगाह पर पोत के अपेक्षित आगमन से कम से कम 3 दिन पहले प्रस्तुत करना होगा, ताकि सीमा शुल्क अधिकारी अधिनियम के	पोत भंग संहिता का पैरा 3.18, 3.19 और 3.20 तथा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को "यथा लागू सीमा शुल्क अधिनियम" से प्रतिस्थापित किया जाए।

प्रस्तावित संशोधन	एसबीसी में मौजूदा प्रावधान (संशोधित), 2013	संशोधन
	<p>तहत सभी सीमा शुल्क औपचारिकताओं को पूरा करने में सक्षम हो सकें।</p> <p>3.19: सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत आवश्यक सभी प्रक्रियाओं और कार्यवाही को पूरा करने के लिए सीमा शुल्क अधिकारी, पोत के आगमन के 24 घंटे के भीतर (सीमा शुल्क विनियमन के अनुसार) पोत पर चढ़ेंगे।</p> <p>3.20: 3.13 और 3.14 के तहत सभी प्रक्रियाओं के पूरा होने पर, पोत पुनर्चक्रणकर्ता सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत विधिवत आंकलित शुल्क का भुगतान करेगा। पोत पुनर्चक्रणकर्ता द्वारा आयात शुल्क चालान प्रस्तुत करके इस तरह के शुल्क के भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करने पर, सीमा शुल्क अधिकारी, 24 घंटे के भीतर, एसएमबी/पत्तन अधिकारियों को एक अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेंगे, जिसमें पोत को समुद्र तट पर रखने की अनुमति देने के लिए उनकी अनापत्ति बताई जाएगी। यह समझा जाता है कि एसएमबी/पत्तन प्राधिकरण ही पोतों को समुद्र तट पर रखने के लिए अनुमति देगा।</p>	

वेंकटेशपति एस
निदेशक

अनुबंध-VIII

पोतभंग संहिता, 2013 के तहत क्षतिपूर्ति समझौता

यह क्षतिपूर्ति समझौता ("समझौता" अथवा "क्षतिपूर्ति समझौता") दिनांक को प्रथम पक्ष ("क्षतिपूर्ति करने वाला पक्ष") नामतः , जो कि पते पर स्थित पंजीकृत कार्यालय के साथ एक पोत मालिक/नकद क्रेता है, तथा द्वितीय पक्ष ("क्षतिपूर्ति प्राप्त करने वाला पक्ष") नामतः , जो कि पते पर स्थित पंजीकृत कार्यालय के साथ एक पोत पुनर्चक्रण क्रेता है, के बीच दिनांक को संपादित और लागू होता है।

जबकि:

क. क्षतिपूर्ति करने वाला पक्ष वर्णन करना चाहता है, और

ख. इस तरह की शर्त के रूप में, क्षतिपूर्ति प्राप्त करने वाला पक्ष क्षतिपूर्ति प्राप्त करना और हानिरहित होना चाहता है, जैसा कि नीचे दिए गए इस क्षतिपूर्ति समझौते में पूरी तरह से निर्धारित किया गया है।

ग. पूर्वगामी और इसमें निहित पारस्परिक अनुबंधों को ध्यान में रखते हुए, जिनकी प्राप्ति और पर्याप्तता को एतद्वारा स्वीकार किया जाता है, इस समझौते के पक्ष निम्नानुसार सहमत होते हैं:

क्षतिपूर्ति करने वाला पक्ष,

(i) क्षतिपूर्ति करने वाले पक्ष के पिछली कृत्यों या चूकों, और विवरण के संबंध में अन्य पक्षों की सूची के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी और सभी दावों, दायित्वों, हानियों, व्ययों, मुकदमों, क्षतियों, निर्णयों, गिरफ्तारियों, मांगों और लागतों (यथोचित कानूनी फीस और व्ययों सहित) से और इनके विरुद्ध: अथवा हानिरहित अन्य पार्टियों की सूची बनाती है।

(ii) किसी भी दुर्घटना, चोट या जीवन की हानि या संपत्ति की हानि या क्षति, समुद्र में प्रदूषण या जुर्माना और दंड, जिसके परिणामस्वरूप, विवरण के कारणों से पूरी तरह से या आंशिक रूप से, इस हद तक कि ऐसी क्षति पूरी तरह से और सीधे क्षतिपूर्ति करने वाले पक्ष की लापरवाही के कारण होती है,

हेतु क्षतिपूर्ति प्राप्त करने वाले पक्ष और अन्य पक्षों की सूची को क्षतिपूर्ति और संरक्षण देने हेतु सहमत होता है।

गवाह के रूप में, इस समझौते के पक्षों ने इस क्षतिपूर्ति समझौते को नीचे हस्ताक्षर करने के लिए अंतिम पक्ष की तारीख के अनुसार विधिवत निष्पादित, वितरित और प्रभावी बनाया है।

क्षतिपूर्ति करने वाला पक्ष

क्षतिपूर्ति प्राप्त करने वाला पक्ष

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

कंपनी का नाम

कंपनी का नाम

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

दिनांक

दिनांक

स्थान

स्थान

गवाहों के नाम/हस्ताक्षर

अनुबंध-IX

नियंत्रित पर्यावरण कार्य परमिट

- एक समय पर केवल एक ही कार्य परमिट जारी किया जाए
- प्रत्येक वांछित कार्य और लोकेशन के लिए पृथक-पृथक परमिट जारी/अनुमोदित किया जाए।
- यदि धारा क और ख में दिए गए किसी प्रश्न का उत्तर “नहीं” है तो पुनर्चक्रण सुविधा के सुरक्षा अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना कार्य शुरू नहीं किया जाएगा।
- समग्र कार्य गतिविधि सीसीटीवी के माध्यम से कवर की जानी चाहिए

पुनर्चक्रण सुविधा का नाम _____

दिनांक _____

स्थान _____

कार्य का उद्देश्य _____

कार्य की लोकेशन _____

यह परमिट: घंटे..... दिनांक से घंटे दिनांक तक वैध है।

(इस परमिट की वैधता 8 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए और कार्य केवल दिन के प्रकाश के दौरान किया जाना चाहिए)

क्या कोई गर्म कार्य संबंधी परमिट जारी किया गया है?

हां/नहीं

यदि “नहीं” तो कारण _____

कार्मिक द्वारा किया गया कार्य

कार्य के लिए उत्तरदायी कार्मिक

सुरक्षा के लिए उत्तरदायी व्यक्ति

क) कार्य शुरू होने से पूर्व जांच सूची

हां/नहीं/लागू नहीं होता

1) क्या कार्य योजना/टूल बॉक्स बैठक आयोजित की गई है और?

☐ ☐ ☐

2) क्या यह क्षेत्र साफ है और तेल और अन्य खतरनाक सामग्री से मुक्त है?

☐ ☐ ☐

क्षेत्र का कितना दायरा साफ किया जाना है (यदि लागू होता है) : _____

☐ ☐ ☐

3) सटा हुआ क्षेत्र साफ है, बाधाओं से मुक्त है?

☐ ☐ ☐

4) क्या गर्म कार्य आवश्यक है?

☐ ☐ ☐

5) क्या प्रयोग में लाए जाने वाले उपकरण सही तरीके से कार्य कर रहे हैं और व्यक्तियों ने उपयुक्त पीपीई पहना है?

☐ ☐ ☐

6) क्या आग बुझाने वाले/जीवन रक्षक उपकरण सही स्थिति में हैं और प्रयोग में लाए जाने के लिए तैयार हैं?

☐ ☐ ☐

7) क्या ऊंचा उठाने वाले (लिफ्टिंग) उपकरण/संयंत्र/क्रेन कार्य करने के लिए व्यवस्थित हैं?

☐ ☐ ☐

8) क्या कार्य योजना के संबंध में सभी संबंधितों के साथ चर्चा की गई है?

☐ ☐ ☐

9) क्या अग्नि अधिकारी से मंजूरी प्राप्त कर ली गई है?

☐ ☐ ☐

10) क्या पत्तन प्राधिकारियों से लिखित में अनुमोदन प्राप्त किया गया है?

☐ ☐ ☐

ख) अतिरिक्त जांच बिन्दु, यदि कुछ किया जाना है

☐ ☐ ☐

ग) कार्य निष्पादन करने वाले व्यक्ति

मैं संतुष्ट हूँ कि सभी प्रकार की सावधानी बरती गई है और कार्य की समग्र अवधि के दौरान सभी प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी जाएगी।

हस्ताक्षर	पदनाम	दिनांक	समय
हस्ताक्षर	पदनाम	दिनांक	समय
हस्ताक्षर	पदनाम	दिनांक	समय

कार्य टीम/अधीक्षण का प्रभारी व्यक्ति

मैं संतुष्ट हूँ कि सभी प्रकार की सावधानी बरती गई है और कार्य की अवधि के दौरान सभी प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी जाएगी।

हस्ताक्षर	रैंक	दिनांक	समय
हस्ताक्षर	रैंक	दिनांक	समय

सुरक्षा अधिकारी द्वारा अनुमोदन

मैं सुरक्षा सावधानियों से संतुष्ट हूँ और एतद्वारा कार्य शुरू करने की अनुमति देता हूँ।

हस्ताक्षर	रैंक	दिनांक	समय
हस्ताक्षर	रैंक	दिनांक	समय

घ. कार्य समाप्ति पर

कार्य सुरक्षात्मक तरीके से पूरा किया गया है, उपस्कर सुरक्षित हैं, परमिट समाप्त हो गया है और सुरक्षा अधिकारी को सूचित किया गया है।

सुरक्षा अधिकारी

समय

दिनांक

यदि जांच सूची की शर्त में कोई परिवर्तन होता है, तो यह परमिट समाप्त हो जाएगा।

टिप्पणियाँ: यह फार्म तब भरा जाए जब कार्य में उच्च तापमान, विद्युत चिन्गारी, खुली लौ अथवा लगातार चिन्गारी निकलने वाला कार्य शामिल हो। यह कार्य शामिल है लेकिन यह वेल्डिंग, बर्निंग, गैस कटिंग और ग्राइडिंग तक सीमित नहीं है।



विशेष परिस्थिति/सावधानी (यदि कोई हो))

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 नवंबर 2023

संकल्प

सं. ई-14011/2/2019-हिंदी— भारत सरकार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दिनांक 09.05.2023 के समसंख्यक पूर्ववर्ती संकल्प में निम्नानुसार संशोधन करने का निर्णय लिया है:

1. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 31.10.2023 के का.ज्ञा.सं. II/20015/26/2014/-रा.भा.(हि.स.स.) द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति में स्वर्गीय श्री ओ.एस.आर.मूर्ति के स्थान पर श्रीमती स्वाति टंडन को गैर-सरकारी सदस्य के रूप में नामित किए जाने के परिणामस्वरूप भारत सरकार एतद्वारा श्री ओ.एस.आर.मूर्ति के स्थान पर श्रीमती स्वाति टंडन को सूचना और प्रसारण मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति में गैर-सरकारी सदस्य के रूप में नामित करती है।

2. सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दिनांक 3.11.2022 और 09.05.2023 के समसंख्यक पूर्ववर्ती संकल्पों में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति संबंधी उल्लिखित सभी निबंधन एवं शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

रविन्द्र कुमार जेना
वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF EDUCATION
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 28th November 2023

No. 9-4/2022-U.3(A)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution Deemed to be University.

2. And whereas, an online application dated 12.08.2022 was submitted on the UGC Portal for conferment of Institution deemed to be University status under de-novo category to Indian Institute of Forest Management (IIFM), Nehru Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh under Section 3 of the UGC Act, 1956. UGC was requested to examine the application and furnish its advice as per UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019.

3. And whereas, UGC, vide its letter No. 29-5/2022 (CPP-I/DU) dated 07.12.2022 informed that the proposal was examined through an Expert Committee. After overall assessment, the Committee recommended for issuance of Letter of Intent (LoI) with certain conditions keeping in view the following proposed courses are in unique and emerging areas of knowledge:

- i. PG programme in Forestry Management,
- ii. PG programme in Sustainability Management,
- iii. PG Programme in Development and Sustainable Finance
- iv. Post Graduate Programme in Climate Resilience and Carbon Management
- v. PG programme in Conservation and Livelihoods,
- vi. PG programme in Sustainable Development.

4. And whereas, the recommendation of the UGC Expert Committee was considered and approved by the Commission in its 563rd meeting (Item No. 2.10) held on 22.11.2022. Considering the advice of UGC, the Ministry issued Letter to Intent (LoI) on 27.12.2022 to Indian Institute of Forest Management (IIFM), Nehru Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh for fulfilment of the following conditions within a period of three years:

- i. IIFM, Bhopal shall prepare detailed syllabi for the courses proposed in the emerging areas;
- ii. IIFM, Bhopal shall recruit faculty with the requisite qualifications;
- iii. IIFM, Bhopal shall create necessary infrastructure for the proposed school;
- iv. The Institute shall revise its DPR, Strategic Vision Plan and Rolling implementation plan accordingly;
- v. The Institute shall obtain NoC/Views of the State Government of Madhya Pradesh.
- vi. IIFM, Bhopal shall submit a letter of commitment from the Ministry of Environment, Forest & Climate Change regarding continuous financial support to the institution even after its declaration as a Deemed to be University.

5. And further whereas, the compliance report submitted by the Institution, vide its letter No. IIFM/DIR/Aca.24/2023/140 dated 17.08.2023 vis-a-vis conditions of LoI was verified and accepted by UGC Expert Committee. The Commission in its 574th meeting (Item No.2.09) held on 03.11.2023 considered and approved the recommendation of the UGC Expert Committee.

6. Now, therefore, on the advice of the UGC, the Ministry of Education, in exercise of powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, hereby declares Indian Institute of Forest Management (IIFM), Nehru Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh as an Institution Deemed to be University under de-novo category for an initial period of five years. The said declaration is subject to the following conditions:

- i. Indian Institute of Forest Management (IIFM), Bhopal shall become compliant with the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023 within a period of six years from the date of issuance of this Notification;

- ii. The deemed to be University status of Indian Institute of Forest Management (IIFM), Bhopal shall be confirmed after five years based on their review and advice of the Commission, as per the provisions of the prevailing Regulations.
- iii. The entire moveable & immoveable assets will be legally transferred in the name of Indian Institute of Forest Management (IIFM), Bhopal within one year of this Notification.
- iv. There shall be no diversion of assets or funds/revenues of the Institution Deemed to be University/or of its constituent teaching units, without prior permission of the UGC and Ministry of Education.
- v. Indian Institute of Forest Management (IIFM), Bhopal shall not engage or indulge in any activities that are of commercial and profit making in nature.
- vi. The academic programmes to be offered at Indian Institute of Forest Management (IIFM), Bhopal shall conform to the norms and standards prescribed by the UGC and the Statutory Councils/Bodies concerned.
- vii. Indian Institute of Forest Management (IIFM), Bhopal shall start new academic Courses/Programmes, Off-Campus(es), Off-Shore Campus(es) only in accordance with the norms and guidelines issued by the UGC, from time to time, on the subject.
- viii. Indian Institute of Forest Management (IIFM), Bhopal shall take appropriate steps to commence research programmes as well as doctoral and innovative academic programmes. The Institute shall not keep confined only to presently new emerging areas but it make endeavor to expand in other areas in accordance with the UGC Regulations / Guidelines as well as National Education Policy-2020.
- ix. Indian Institute of Forest Management (IIFM), Bhopal shall take all the required steps to get all the eligible academic courses/programmes rated for valid accreditation by National Board of Accreditation (NBA) and the Institute to get valid accreditation by National Assessment and Accreditation Council (NAAC), as the case may be, in terms of the provisions as contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023, as amended from time to time.
- x. All the prescribed norms and procedures of the Statutory Councils concerned in the matter of admission of students, intake capacity of students, renewal of approval to the academic course / programme, revision of intake capacity of students, starting of new courses / programmes, etc. shall continue to be in force, and shall be adhered to by Indian Institute of Forest Management (IIFM), Bhopal.
- xi. Indian Institute of Forest Management (IIFM), Bhopal shall submit its revised Memorandum of Association (MoA) / Rules to UGC/ Ministry of Education as per the provisions of the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023 by June, 2024. As and when necessary, the Institute shall update or revise or modify its MoA / Rules, as per the provisions of the prevailing Regulations.
- xii. Indian Institute of Forest Management (IIFM), Bhopal shall follow the fee structure as per the Rules and Regulations of the UGC and relevant Statutory Councils.
- xiii. Indian Institute of Forest Management (IIFM), Bhopal shall participate in annual Indian rankings issued by National Institutional Ranking Framework (NIRF) of this Ministry.
- xiv. Indian Institute of Forest Management (IIFM), Bhopal shall compulsorily create Academic Bank of Credits (ABC), identities of their students and upload their credit score in digital lockers and ensure that the credit scores are reflected in ABC Portal and adopt Samarth e-Gov.

AMBRISH KUMAR SHARMA
Under Secretary

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING & WATERWAYS

New Delhi - 110001, the 24th November 2023

ORDER

No. SY-19014/6/2023-SBR—In exercise of the powers conferred by para 8.4.1 of the Ship Breaking Code (Revised), 2013, the Government of India in the Ministry of Ports, Shipping & Waterways hereby amends following clauses in the Ship Breaking Code (Revised), 2013, as given in the Schedule to this Order.

Proposed Amendment	Existing Provision in SBC (Revised), 2013	Amendment
In Chapter III : Arrival of Vessel, Anchoring and Beaching Process Clause No. 3.5 (K) :-	Undertaking from the shipowner that they will submit Non-Encumbrance certificate within 7 days from the the date of anchorage of vessel at outer anchorage. It is made clear that permission for beaching will be granted by State Maritime Board only on production of the Non-Encumbrance.	To include the paragraph "A notarized indemnity agreement shall be executed between the Ship Owner/Cash buyer and the Ship Recycler in the given format as per Annexure VIII prior to recycling, so that any claims or maritime lien in the later stage of ship recycling are avoided". in clause 8.3.5 (a) of SBC 2013 in "Chapter VIII - Miscellaneous and Penalty Provisions". Indemnity agreement as per Annexure VIII attached.
In Chapter VI : General Instruction for Safety Health and Environment Compliance for stakeholders involved in Ship Recycling. Clause No. 6.5.5:	There shall be no burning of any material on the plot/yard/inertial Zone.	The matter to be taken as Controlled heating and not burning. The following text is to be added in the existing Clause 6.5.5 "Controlled heating of Hub of Propeller for removal of Shafting allowed after working Hours with a permit arrangement. The format of the permit to work is as per Annexure IX"
In Chapter III : Arrival of Vessel, Anchoring and Beaching Process Clause 3.23	After completion of all these formalities and on payment of all dues/duty on the vessel, the Customs Authority would give out of charge and clear the ship for recycling.	Text to be deleted in clause 3.23: "After completion of all these formalities and on payment of all dues/duty on the vessel, and on payment of all dues/duty on the vessel, the Customs Authority would give out of charge and clear the ship for recycling".
In Chapter III : Arrival of Vessel, Anchoring and Beaching Process Clause 3.18, 3.19 & 3.20	3.18: Customs procedures:-The Ship Recycler shall also submit all documents and details as are required by the Customs Authorities under the Customs Act, 1962, at least 3 days prior to the expected arrival of the vessel at anchorage, to enable the Customs Authorities to complete all customs formalities under the Act. 3.19: Customs Officers shall board the vessel within 24 hours of ship's arrival (as per Customs regulation) to complete all procedures and processes required under the Customs Act,1962. 3.20: On completion of all procedures under 3.13 and 3.14, the Ship Recycler will pay the duty, as duly assessed under the Customs Act,1962. On the ship recycler producing the proof of payment of such duty by production of the Import Duty Challan, the Customs Authorities shall, within 24 hours, issue a No Objection Certificate to the SMB/ Port Authorities, stating their No Objection to grant of permission to beach the vessel. It is understood that it is the SMB/ Port Authority which shall grant permission for beaching of vessels.	Para 3.18, 3.19 and 3.20 of the Ship Breaking code, "Custom Act 1962" to be replaced as "The Custom Act as applicable".

VENKATESAPATHY S
Director

Annexure-VIII

Indemnity agreement under Ship Breaking Code 2013

THIS INDEMNITY AGREEMENT (the “Agreement” or this “Indemnity Agreement”), is made and entered into as of this date, by and between party name _____ (the “Indemnifying Party”), a shipowner/cash buyer with a registered office located at address and party name 2, a ship recycler buyer with a registered office located at address (“the Indemnified Party”).

WHEREAS:

- a. The Indemnifying Party wishes to description, and
- b. As a condition of such, the Indemnified Party wishes to be indemnified and held harmless, as more fully set forth in this Indemnity Agreement below.
- c. In consideration of foregoing, and of the mutual covenants contained herein, the receipt and sufficiency of which are hereby acknowledged, the parties to this Agreement hereby agree as follows:

The Indemnifying Party herewith agree to indemnify and protect the Indemnified party, and list of other parties harmless from and against any and all claims, liability, loss, expenses, suits, damages, judgments, arrests, demands, and costs (including reasonable legal fees and expenses) arising out of

- (i) the past acts or omissions of the Indemnifying Party, and list of other parties in connection with description: or
- (ii) any accident, injury or loss of life or loss or damage of property, pollution at sea or fines and penalties which may result, in whole or in part, by reasons of description except to the extent that such damage is due solely and directly to the negligence of the Indemnified Party.

IN WITNESS WHEREOF, the parties to this Agreement have caused this Indemnity Agreement to be duly executed, delivered and effective as of the date of the last party to sign below.

Indemnifying Party

Indemnified party

Name of Authorised signatory

Name of Authorised signatory

Company Name

Company Name

Signature

Signature

Date

Date

Place

Place

Witnesses Name/signature

Annexure IX

CONTROLLED ENVIRONMENT WORK PERMIT

- ONLY ONE WORK PERMIT SHOULD TO BE ISSUED AT A TIME
- A SEPARATE PERMIT SHOULD BE ISSUED/ APPROVED FOR EACH INTENDED TASK AND LOCATION
- WORK SHALL NOT BE TAKEN UP IF ANSWER IS “NO” TO ANY QUESTION IN SECTION A & B WITHOUT PRIOR APPROVAL OF SAFETY OFFICER OF THE RECYCLING FACILITY
- THE WHOLE WORK ACTIVITY MUST BE COVERED BY CCTV.

Name of the Recycling facility _____

Date _____

Place _____

Purpose of work
_____Location of work
_____This permit is valid: From _____ hrs. Date _____ To _____ hrs.
Date _____

(Validity of this permit should not exceed 8 hours and work should only be carried out in Day light)

Has any hot work permit been issued? YES/NO

Reason if "NO"
_____Personnel carrying out work
_____Personnel responsible for work
_____Person responsible for
safety _____

A) Check list prior commencement of work

Yes No N/A

- | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Has work plan/Tool box meeting been held and risk assessment completed? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Is the area clean and clear of oil and other dangerous material? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Radius of area are to be cleaned (if applicable) : _____ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Adjacent area cleaned, free of hazards,? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Is hot work necessary? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Is equipment to be used in good order and men wearing suitable PPE? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Are fire fighting/life saving appliances in good order and in readiness for use? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Is the lifting devices/equipment/Crane in order | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Is the Work plan discussed with all concerned? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. Has approval been obtained from the Fire Officer? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. Has any written approval been obtained from port authorities? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

B) Additional Checks if any to be carried out

☐ ☐ ☐

C) Persons Carrying out Work

I am satisfied that all precautions have been taken and all safety arrangements will be maintained for entire duration of work.

Signature	Designation	Date	Time
Signature	Designation	Date	Time
Signature	Designation	Date	Time

Person in Charge of Work Team/ Supervision

I am satisfied that all precautions have been taken and all safety arrangements will be maintained for entire duration of work.

Signature	Rank	Date	Time
-----------	------	------	------

Approval by Safety Officer

I am satisfied with safety precautions and hereby give my permission to commence work.

Signature	Rank	Date	Time
-----------	------	------	------

D. On completion of work

The work has been safety completed, equipment secured, permit closed and safety officer has been informed.

Safety Officer Time _____ Date _____

THIS PERMIT IS RENDERED INVALID SHOULD ANY OF THE CONDITION NOTED IN THE CHECKLIST CHANGE

Notes: This form is to filled when work including high temperature, electric arc. Open flame or continuous source of sparks. This work includes but is not limited to welding, burning, Gas cutting and grinding.



Special condition / Precaution (if any)

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, 23 November 2023

Resolution

No. E-14011/2/2019-Hindi: The Government of India has decided to amend the Ministry of Information and Broadcasting's earlier Resolution of even number dated 09.05.2023 as follows:

1. Consequent upon the nomination of Smt. Swati Tandon as Non-Official Member of the Hindi Advisory Committee of the Ministry of Information and Broadcasting in place of late Shri O.S.R. Murthy by Department of Official Language, Ministry of Home Affairs vide their Office Memorandum No.II/2001526/2014/-रा.भा.(हि.स.स) (dated 31.10.2023, the Government of India hereby nominates Smt. Swati Tandon as a Non-Official Member of the Hindi Advisory Committee of the Ministry of Information and Broadcasting in place of Shri O.S.R. Murthy.

2. All the terms and conditions regarding the Hindi Advisory Committee of the Ministry of Information and Broadcasting mentioned in this ministry's even number previous resolutions dated 3.11.2022 and 09.05.2023 respectively shall remain the same.

RABINDRA KUMAR JENA
Sr. Economic Adviser